ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता स्वरोजगार एवं सशक्तिकरण

अभिजीत कुडेरिया[1] और **चेतना पाठक**[2]

“ आजीविका उद्यमिता ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। पारंपरिक कृषि आय के सीमित अवसरों के बीच स्थानीय संसाधन, कौशल विकास और नवाचार पर आधारित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ग्रामीण परिवारों को स्थायी आय प्रदान कर रहे हैं। पशुपालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण तथा हस्तशिल्प जैसी गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक समावेशन और स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। किसान उत्पादक संगठन सामूहिक विपणन, तकनीकी सहयोग और बेहतर बाजार उपलब्धता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। वहीं, ई-मार्केटिंग, डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया जैसी तकनीकों ने ग्रामीण उद्यमियों को सीधे बाजार से जोड़कर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई है। इस प्रकार, आजीविका उद्यमिता आत्मनिर्भर और सतत ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला बन रही है। ”

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था करोड़ों परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है। लंबे समय तक कृषि और दैनिक मजदूरी तक सीमित आय के विकल्प आज बदलती आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं रह गए हैं। ऐसे में आजीविका उद्यमिता ग्रामीण विकास का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है, जो स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, कौशल विकास और नवाचार के जरिए ग्रामीण समुदायों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बना रही है। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2010-11 में इन उद्यमों की संख्या लगभग 1 करोड़ थी, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर करीब 1.92 करोड़ तक पहुंच गई। इन उद्यमों ने महिलाओं के लिए 89 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित किए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक भागीदारी को नई गति मिली है। इस प्रकार, आजीविका उद्यमिता आत्मनिर्भर भारत और सतत ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला बनती जा रही है।

आजीविका उद्यमिता का तात्पर्य ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से है, जो विशेष रूप से ग्रामीण, महिला, युवा, आदिवासी और कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य लाभ के साथ-साथ समावेशन, स्थायित्व और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा एवं डिजिटल उद्यम इसके प्रमुख घटक हैं।

[1]पीएच.डी. शोधार्थी; [2]सहायक प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर-482004

कृषि आजीविका का मूल आधार है, किंतु केवल कच्चे उत्पादों की बिक्री से सीमित आय प्राप्त होती है। मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन से किसानों की आय में काफी वृद्धि संभव है। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक एवं प्राकृतिक खेती जैसे उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी से अधिक लाभ देने वाले आजीविका मॉडल हैं। किसान उत्पादक संगठन किसानों को सामूहिक शक्ति, बाजार तक पहुंच और तकनीकी सहयोग प्रदान कर आय सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वहीं महिलाओं के लिए आजीविका उद्यमिता सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं बचत, ऋण, उत्पादन और विपणन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए आजीविका उद्यमिता बेरोजगारी की समस्या का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती है, विशेषकर जब इसे कौशल विकास और स्थानीय अवसरों से जोड़ा जाए।

डिजिटल तकनीक और नवाचार

डिजिटल इंडिया पहल ने आजीविका उद्यमिता को नई दिशा दी है। ई-मार्केटिंग, डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ग्रामीण उद्यमी सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाएं आजीविका आधारित नवाचार को प्रोत्साहित कर रही हैं।

लघु उद्यम में महिलाओं का बड़ा योगदान

आज की आजीविका उद्यमिता केवल आय पर नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर भी केंद्रित है। हरित उद्यमिता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु सहिष्णु कृषि और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन पद्धतियां दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करती हैं।

सतत विकास और उद्यमिता के प्रमुख स्तंभ

- **मूल्य संवर्धन:** ग्रामीण उद्यमिता में केवल कच्चा उत्पाद बेचने के बजाय उसका प्रसंस्करण कर अधिक मूल्य प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, टमाटर को सीधे बाजार में बेचने की बजाय उससे सॉस, प्यूरी या पाउडर तैयार करने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। मूल्य संवर्धन से उत्पादों की मांग, भंडारण क्षमता और बाजार मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
- **डिजिटल एकीकरण:** डिजिटल तकनीकों ने ग्रामीण उद्यमिता को नई दिशा प्रदान की है। आज छोटे किसान, बुनकर, हस्तशिल्पी और महिला स्वयं सहायता समूह सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफार्म और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से सीधे ग्राहकों तक पहुंच बना रहे हैं। इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम

मशीनीकरण का बढ़ता दायरा

सफलताएं

- महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसान श्री विलास शिंदे ने यह महसूस किया कि अंगूर उत्पादक किसानों को बिचौलियों के कारण उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। इसी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने किसानों को संगठित कर 'सह्याद्रि फार्म्स' की स्थापना की। आज यह संस्था हजारों किसानों को बेहतर बाजार, प्रसंस्करण और निर्यात सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इनकी पहल ने यह साबित किया कि सामूहिक प्रयास खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल सकते हैं।
- इसी प्रकार बिहार के मुंगेर जिले की बीना देवी ने घर के एक छोटे से कमरे से मशरूम उत्पादन शुरू किया। सीमित संसाधनों के बावजूद इन्होंने अपने परिश्रम और नवाचार से इसे सफल उद्यम में परिवर्तित कर दिया। आज वे न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, बल्कि गांव की सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से भी जोड़ चुकी हैं। इनके कार्यों के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।
- छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह भी ग्रामीण उद्यमिता की प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभरे हैं। ये महिलाएं फूलों के अपशिष्ट और गोबर से अगरबत्ती तथा प्राकृतिक पेंट तैयार कर रही हैं। आधुनिक मशीनों और ऑनलाइन विपणन की मदद से उनके उत्पाद अब बड़े बाजारों तक पहुंच रहे हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत हुई है।

सरकारी प्रयास

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लखपति दीदी योजना का उद्देश्य देश की करोड़ों महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए व्यवसाय शुरू करना पहले की तुलना में अधिक सरल हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उत्पन्न किए हैं।

प्रसंस्करण क्षेत्र में संलग्न महिलाओं की प्रभावी भूमिका

हुई है और उत्पादों का उचित मूल्य मिलने लगा है। 'ई-श्रम' जैसे डिजिटल प्लेटफार्म ग्रामीण श्रमिकों और उद्यमियों को पहचान, बाजार और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

- **कौशल प्रशिक्षण:** ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रम आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य व्यावसायिक कौशल विकसित किए जा रहे हैं। इससे युवाओं में स्वरोजगार की भावना बढ़ रही है और वे छोटे स्तर पर सफल उद्यम स्थापित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं।

आजीविका उद्यमिता ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और सतत विकास का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। स्थानीय संसाधनों, कौशल विकास, डिजिटल तकनीकों और सरकारी सहयोग के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को स्थायी आय और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उचित नीतिगत समर्थन, वित्तीय सहायता और संस्थागत सहयोग के जरिए आजीविका उद्यमिता आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भविष्य में शोध-आधारित नवाचारों, क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों और बाजारोन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से इस मॉडल को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। ■

यांत्रिकीकरण का बढ़ता दायरा

निवेदन

लेखक बंधु *खेती* पत्रिका के लिए अपने लेख और संबंधित फोटो, कवरिंग लैटर के साथ सिर्फ निम्न पोर्टल पर ही अपने मोबाइल नम्बर के साथ भेजें। ध्यान रखें कि फोटो जेपीजे फॉर्मेट में और उच्च रेज्योल्यूशन की हों। लेख में अधिकतम 1200 शब्दों की संख्या रखने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी भेज सकते हैं।

हमारा पोर्टल है :
epatrika.icar.org.in

–संपादक